

न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार वाष्णीय, आर. ए. एस.

अपील संख्या:- 28 / 2017 (225 आर. टी. एक्ट)

आर.सी.एम.एस. संख्या :- 2017 / 00174

उनवान

1. पूरन पुत्र बालूराम जाति धाकड निवासी बझेरा कलॉ तहसील वैर जिला भरतपुर(मृतक)
 - 1/1. गंगादेई उम्र 80 वर्ष वेवा पूरन
 - 1/2. बनैसिंह उम्र 59 वर्ष पुत्र पूरन
 - 1/3. भंवर सिंह उम्र 57 वर्ष पुत्र पूरन
 - 1/4. भूदेव सिंह उम्र 53 वर्ष पुत्र पूरन
 - 1/5. चरन सिंह उम्र 46 वर्ष पुत्र पूरन
 - 1/6. केहरी सिंह उम्र 43 वर्ष पुत्र पूरन
 - 1/7. कुँवर सिंह उम्र 38 वर्ष पुत्र पूरन

जाति धाकड निवासी बझेरा कला तहसील
वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर।
2. तहसीलदार तहसील वैर।
3. ग्राम पंचायत बझेरा कलॉ जरिये सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत बझेरा कलॉ तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अंतर्गत धारा 225 राज0 काश्त0अधि0
विरुद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
वैर दिनांक 20.05.2017 उनवानी पूरन बनाम
सरकार मु0न0 36 / 13

अभिभाषकगण :-

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :- 25.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के आदेश दिनांक 20.05.2017 के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण

के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादी ने मूल दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध रैस्प0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम बझेरा कलॉ तहसील वैर के अपीलाण्ट/वादी खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी संवत 2012-16 से चले आ रहे हैं एवं विवादित आराजी अपीलाण्ट/वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खुद काश्त दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में खुद काश्त दर्ज होने के कारण अपीलाण्ट/वादी को धारा 29(1) सपठित धारा 5(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदारी हकूक प्राप्त हो चुके हैं। परन्तु जमींदारी जब्त होने के पश्चात् खिलाफ कानून व मौके के विरुद्ध, अपीलाण्ट/वादी की लाइल्मी में विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में मकबूजा चारागाह दर्ज हो गयी है। उक्त गलत इन्द्राजो के कायम रहने के कारण अपीलाण्ट/वादी को खातेदार काश्तकार ना मानकर, एक अतिक्रमी की संज्ञा दी जा रही है, जिसका रैस्प0/प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्प0डेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील सीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, वैर खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी अपीलाण्ट की पुश्तैनी घरू खेवट एवं खुद काश्त की आराजी रही है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने एवं राजस्थान जमींदारी एवं विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आने के समय अपीलाण्ट के पुरखों की मिलकीयत व खुद काश्त में रही है। इसलिये उन्हें इस आराजी पर उक्त अधिनियमों के प्रावधानानुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं देकर खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है। विवादित आराजी कभी बंजड अथवा चारागाह नहीं रही है। हमेशा से अपीलाण्ट व उनके पूर्वजों की खुदकाश्त व खातेदारी में रही है। इसलिये राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के चारागाह भूमि गलत अंकित किया गया है। अदालत तहत ने पूर्व के इन्द्राजों को नजर अंदाज कर केवल वर्तमान इन्द्राजों पर भरोसा कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, मूल दावे के निर्णय होने तक रैस्प0 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।
4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कभी कब्जा काश्त रहा है। विवादित आराजी की किस्म राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों

